भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2089

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पेरम्बलूर में पीएम-अभिम अवसंरचना परियोजनाएं

†2089. श्री अरुण नेहरू:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु के पेरम्बलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिम) के अंतर्गत अवसंरचना परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत जारी की गई और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत उन्नत की गई सुविधाओं की संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका क्या अनुमानित प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिम) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) घटक शामिल हैं, और इसे स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी, जन स्वास्थ्य कार्रवाई और स्वास्थ्य अनुसंधान को एकीकृत करने वाले सुधारों के माध्यम से भारत की जन स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए लागू किया गया है, जिससे महामारियों और अन्य जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए जन स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता बढ़ती है।

योजना के सीएसएस घटक के तहत, तमिलनाडु राज्य को 708 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (शहरी-एएएम), जिला स्तर पर 38 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और जिला अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेज स्तर पर 39 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों (सीसीबी) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए 1656.32 करोड़ रुपये की राशि हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

राज्य द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पेरम्बलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में, योजना के सीएसएस घटक के अंतर्गत, पेरम्बलूर जिले के लिए क्रमशः 23.75 करोड़ रुपये और 1.25 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत पर एक 50-बेड वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) और एक एकीकृत जन स्वास्थ्य

प्रयोगशाला (आईपीएचएल) को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, पेरम्बलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला अस्पताल, कुलीथलाई में एक एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (आईपीएचएल) को भी पीएम -अभिम के तहत अनुमोदित किया गया है, जिसका निर्माण पूरा हो चुका है और सुविधा केंद्र क्रियाशील कर दिया गया है।

पीएम-अभिम के तहत, अनुमोदित कार्यकलापों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एकमुश्त आधार पर निधियाँ जारी की जाती हैं, जिससे वे अपनी आकलित आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार इन निधियों का उपयोग कर सकें। पीएम-अभिम की शुरूआत से लेकर वित्त वर्ष 2026-27 (13.07.2026 तक), इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के लिए जारी केंद्रीय धनराशि और व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**केंद्रीय धनराशि (करोड़ रु में)**	**व्यय (करोड़ रु.में)**
2021-22	17.45	29.08
2022-23	150.42	183.35
2023-24	279.36	389.37
2024-25	224.99	512.33
2025-26	172.51	283.44
2026-27	23.45	0.00

टिप्पणी:

1. उपरोक्त धनराशि केंद्र सरकार अनुदानों से संबंधित हैं और इनमें राज्य के हिस्से का अंशदान शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय धनराशि 13.07.2026 तक अद्यतन किया गया है और अनंतिम है।
2. व्यय में केंद्रीय धनराशि, राज्य धनराशि और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि के सापेक्ष व्यय शामिल है।
3. व्यय राज्य द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए व्यय 31.05.2026 तक अद्यतन किया गया है।

राज्य ने यह भी सूचित किया है कि स्वीकृत परियोजनाओं के समय पर पूर्ण होने को सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी, गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा समय पर कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए एक कार्यक्रम प्रबंधन परामर्शी (पीएमसी) को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, परियोजना की प्रगति की निगरानी और कार्यान्वयन में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन), जो निर्माण कार्यों के नोडल अधिकारी भी हैं, द्वारा सप्ताह में दो बार समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। साथ ही, प्रगति की समीक्षा करने, महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने और स्वीकृत अवसंरचना के समय पर पूर्ण तथा कार्यशील होने को सुनिश्चित करने के लिए मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, तमिलनाडु की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

******